

नीति आयोग ने तैयार किया 'स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स'

स्कूली शिक्षा में केरल अक्वल उत्तराखंड दसवें स्थान पर

हरिकिशन शर्मा • नई दिल्ली

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहद खराब है। नीति आयोग ने 'स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स' तैयार किया है जिसमें 20 बड़े राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर जबकि केरल पहले, राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। खास बात यह है कि बड़े राज्यों में झारखंड 16वें और बिहार 17वें स्थान पर है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर का प्रदर्शन इन दोनों राज्यों से भी खराब है।

सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की है। इस इंडेक्स की रिपोर्ट पर बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में विचार-विमर्श किया गया। जल्द ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 30 इंडीकेटर के आधार पर 20 बड़े राज्यों और आठ छोटे राज्यों की रैंकिंग की गई है। सबसे खराब प्रदर्शन वाले पांच राज्यों में झारखंड, बिहार, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। हालांकि बंगाल ने इस इंडेक्स में भाग नहीं लिया है। यह इंडेक्स 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें स्कूली विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों (लर्निंग आउटकम) के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। इसे तैयार करने में विश्व बैंक और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों

बड़े राज्यों का प्रदर्शन

1.केरल	11.हरियाणा
2.राजस्थान	12.ओडिशा
3.कर्नाटक	13.छत्तीसगढ़
4.आंध्र प्रदेश	14.तेलंगाना
5.गुजरात	15.मध्य प्रदेश
6.असम	16.झारखंड
7.महाराष्ट्र	17.बिहार
8.तमिलनाडु	18.पंजाब
9.हिमाचल प्रदेश	19.जम्मू-कश्मीर
10.उत्तराखंड	20.उत्तर प्रदेश



की मदद भी ली गई है।

सूत्रों ने कहा, जिन आठ छोटे राज्यों की रैंकिंग अलग से की गई है उनमें मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। जिन छह मानकों पर राज्यों की रैंकिंग की गई है उनमें शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा के लिए ढांचागत सुविधाएं और प्रशासन जैसे इंडीकेटर शामिल हैं। राज्यों की रैंकिंग करते समय इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि स्कूलों में जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उससे वे कितना सीख रहे हैं। मालूम हो कि इससे पूर्व नीति आयोग वाटर इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स पर भी राज्यों की रैंकिंग जारी कर चुका है।